भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 312

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना

***312. श्री मितेश पटेल (बकाभाई):**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यनीतियां अपनाई गई हैं कि उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से 14 प्रमुख सेक्टरों में अपेक्षित निवेश और उत्पादन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में प्रभावी ढंग से सहयोग मिले और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विशेषतः व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना हेतु वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश को आकर्षित करना; दक्षता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने की किफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ये स्कीमें अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता रखती हैं।

पीएलआई स्कीम से देश के एमएसएमई ईकोसिस्टम पर क्रमिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रमुख इकाइयां स्थापित की जाएंगी, उनमें संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में एक नया आपूर्तिकर्ता/विक्रेता आधार सृजित करने की संभावना है। इन सहायक इकाइयों में से अधिकांश एमएसएमई क्षेत्र में स्थापित होने की संभावना है। विभिन्न पीएलआई स्कीमों के तहत अब तक अनुमोदित 764 आवेदनों में से, एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत 176 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है जैसे बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मा, दूरसंचार, व्हाइट गुड्स, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और ड्रोन इत्यादि।

(ख) : व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम को 6,238 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है।

******